an>

Title: The Minister of State of Skill Development and Entreprenureship made a statement regarding Government Business for the week commencing the 8th March, 2016 and submission made by Members.

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि मंगलवार, 8 मार्च, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:

1. आज की कार्य-सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. वर्ष 2016-17 के लिए लेखानुदान मांगों (रेल) और वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) से सम्बन्धित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार करना और पारित करना।

3. वर्ष 2016-17 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा।

4. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:

(क) वर्ष 2016-17 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य)

(ख) वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)

5. सम्बन्धित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

6. अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 पर विचार और पारित करना।

7. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016 पर विचार और पारित करना।

8. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार और पारित करना।

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam Speaker, I intend to raise the following two matters on the submission for the next week. Kindly grant permission and oblige.

1. Fresh guidelines should mandate earmarking of SCP/TSP funds from plan outlays at least 6 months before the commencement of the next financial year and schemes where benefits to SCs/STs are merely notional not be included in the Sub Plans. A specific institution should be set-up at Centre and State levels to allocate SCP/TSP funds to the Ministries/Departments, duly taking into consideration the developmental needs of SCs/STs, so that Ministries/Departments can clearly show the schemes for the development of SCs/STs separately under the separate budget minor heads. The same institution should also be responsible for approvals and issue of sanctions and effective implementation and monitoring of the SCP/TSP. SCP/TSP funds should be deployed with particular focus on education, income generation and access to basic amenities in SC/ST localities in the country. Funds should be non-lapsable and non-divertible. SCP/TSP funds should be channelised only to such schemes where tangible benefits accrue to SC/ST individuals or households or groups or localities. Schemes taken up under the SCP/TSP should be closely monitored and the information should be hosted in the public domain so as to enable anyone to track every scheme. The NCSC and NCST should be strengthened with adequate professional expertise and provided with supporting manpower to undertake independent evaluation of SCP schemes of the Central Ministries and to give feedback to these Ministries. The NCSC can also recommend schemes which have the potential to best address the development needs of SCs to the concerned Central Ministries for inclusion in their Annual SCP Plans. The Nodal Department may also be empowered to clear the schemes proposed by the departments under the SCP only if the schemes fulfill the criteria of securing direct benefits to SC individuals,

households or localities.

2. It has been observed that after retirement, employees continue to lead trade unions and/or associations of working employees. Complaints are being received from aggrieved employees in Ministry of Defense and Railways in particular. The Government must immediately take steps to rectify this practice.

Thanking you.

माननीय अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं सत्र के अगले सप्ताह में निम्नलिखित विषय संसद के संज्ञान में लाना चाहता हूं:

1. आज बिहार के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की, विशेष तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 85 एवं 101 की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गई है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाओं में जान-माल की काफी क्षति हो रही है तथा प्रदेश सरकार इस विषय पर आंख बन्द करके बैठी हुई है। यहां तक कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदान को प्रदेश की सरकार अक्षमता के कारण खर्च नहीं कर पा रही है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि इस सन्दर्भ में एक केन्द्रीय जांच टीम के द्वारा निरीक्षण करा करके प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, विशेष तौर पर 101 तथा 85 को सुधारा जाये, जिससे कि यातायात सुगम हो सके।

2. आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सौर ऊर्जा पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार से मेरा आग्रह है कि बिहार प्रदेश में बिजली के खस्ताहाल को देखते हुए बिहार में सौर ऊर्जा का प्लांट हर पंचायत स्तर पर लगाया जाए। विशेष तौर पर सिवान एवं सारण जिले के महाराजगंज क्षेत्र में स्थापित किया जाये, जिससे कि प्रदेश की जनता को बिजली की समस्या से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।

12.15 hours